PRIME MINISTER'S OFFICE; THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, I beg to move:

That the suspension of Shri Subhash Prasad Yadav from the service of the House with effect from 9th March 2010 for the remaining part of the current Session be terminated.

The question was put and the motion was adopted.

GOVERNMENT BILLS

The Cost and Works Accountants (Amendment) Bill, 2010

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Cost and Works Accountants Act, 1959.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, I introduce the Bill.

The Chartered Accountants (Amdnement) Bill, 2010

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Chartered Accountants Act, 1949.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, I introduce the Bill.

The Company Secretaries (Amendment) Bill, 2010

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Company Secretaries Act, 1980.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, I introduce the Bill.

DISCUSSION ON WORKING OF MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश) : थैंक्यू सर। आज एक बहुत ही important Ministry, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation की working के ऊपर जो, discussion है, उसकी शुरुआत करने के लिए आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज हम देखते हैं कि जो urban

population 2001 में 28.61 परसेंट थी, वह 2011 में बढ़कर 32 करोड़ होने जा रही है और 2021 में इसके 53 करोड़ होने का अंदाजा है। यह population का बहुत बड़ा challenge है, जो urban areas के ऊपर नजर आ रहा है। इसका कारण यह है कि आज तक इस देश में हमारी जो सरकार बनी, उसकी जो नीति रही है, वह गांवों के विरुद्ध रही है। गांवों में quality of education, health services, transport, power supply, जो facilities की lacking है, उसकी वजह से दो तरह के लोग urban area की तरफ जा रहे हैं। एक वे हैं, जो महसूस करते हैं कि गांवों में basic facilities नहीं हैं। उनके पास साधन हैं, इसलिए वे गांव छोड़ कर शहर की तरफ जा रहे हैं। दूसरे वे हैं, जो इस देश में सामंतवादी आतंकवाद के शिकार हैं। साधन सम्पन्न और साधनहीन, दो तरह के लोगों का urban area की तरफ flow है। 11th Five Year Plan में यह अंदाजा लगाया गया कि housing की दिशा में हमारी requirement 3,61,318 करोड़ है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश की सरकार ने slum free भारत बनाने का संकल्प भी अपने प्रोग्राम में दर्शाया है। कौन लोग हैं, जो slum में रहते हैं? हमारा मानना है कि हमारे देश में 3 किस्म के शरणार्थी हैं। पहली किस्म के शरणार्थी वे हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान से उठ कर आए। उनको हमारे देश की सरकार ने संभाला।

दूसरी किस्म के शरणार्थी वे होते हैं, जब भारत की किसी भी स्टेट में टैरिरिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं और उस समय उस एक्टिविटी के शिकार लोग अपने स्टेट को छोड़कर आते हैं। सरकार उनके लिए भी नीति बनाती है। जैसे पीछे कुछ लोग जम्मू-कश्मीर को छोड़कर आए, किसी समय कुछ लोग पंजाब छोड़कर आए थे, कुछ और भी ऐसे दूसरे स्टेट्स हैं, जिन्हें छोड़-छोड़ कर लोग शहरों की तरफ आए।

तीसरी किस्म के शरणार्थी वे हैं, जो सामंतवादी आतंकवाद के शिकार हो कर गांव छोड़ते हैं। सरकार के मुताबिक तो उनकी पॉपुलेशन कम है, क्योंकि दुनिया वालों को मुंह दिखाने के लायक रहने के लिए भी कई बार सरकारी आंकड़े कम करके दिखाए जाते हैं। हमारे मुताबिक, जो लोग सामंतवादी आतंकवाद के शिकार हो कर शहरों में आ कर रह रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन करीब 12 करोड़ है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि हरियाणा के हिसार जिले में सामंतवादियों ने दलितों के 16 घर जला दिए। इस दुर्घटना में एक बाप और एक बेटी को जिंदा जला दिया गया और साथ ही एक अन्य की भी मौत हुई एवं लगभग 20 लोग अभी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इससे पहले भी अलग-अलग प्रदेशों में ऐसी सामंतवादी घटनाएं होती रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले पंजाब के भटिंडा जिले में, तलवंडी साबो सब डिवीज़न में भगवान पुर गांव में दलितों के घरों को तोड़ा गया और उनको तोड़ने के बाद सामंतवादियों के ऊपर मुकदमा कायम हुआ। मुकदमा कायम होने के बाद जिले के डिप्टी कमिश्नर ने दोबारा घर बनाने के लिए, इन 12 घरों के लिए, 1,25,000 रुपए का एमाउंट मंजूर किया, जिसमें से किसी को 10,000 रुपए दिए गए, किसी को 15,000 रुपए दिए गए। जब 24 तारीख को उन्होंने अपने घर बनाने शुरू किए, तो लोकल पुलिस ने वहां जाकर सामंतवादियों को प्रोटेक्शन दिया और दलितों के ऊपर दफा 307 के तहत सरकारी काम में विघ्न डालने का मुकदमा लगा दिया गया, साथ ही औरतों, बच्चों एवं बुजुर्गों को जेल में फेंक दिया गया। ऐसी सामंतवादी घटनाएं देश के कोने-कोने में होती रहती हैं और हमारी सरकारें सामंतवादियों की पीठ थपथपाती नजर आती है, जिसके कारण गांवों की आबादी शहरों की तरफ आती नजर आ रही है।

जब वे गरीब लोग शहरों में आकर रहते हैं, तो उनके पास संसाधन नहीं होते, पैसा नहीं होता इसलिए वे झुग्गी-झोंपड़ी में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ऐसे में उनकी तरफ सरकार का कोई नजरिया, कोई नीयत या कोई नीति नहीं होती है। आज भी हमें यह सब देखने को मिल रहा है। 12 फरवरी, 2010 को दिल्ली के हाई कोर्ट ने भी सरकार को यह आदेश दिया कि दिल्ली में स्लम्स में रहने वाले जो लोग हैं, उनको बसाने का प्रबंध किया जाए। कॉमन वेल्थ गेम्स के नाम पर हमारी सरकार दुनिया को यह दिखाना चाहती है कि हमारा देश भारत ही सबसे अच्छा देश है। लेकिन दुनिया के सामने भारत का अच्छा नक्शा पेश करने के लिए झुग्गी-झोंपड़ी वालों को अच्छे आल्टरनेटिव हाउस बनाकर नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि उनको वहां से उजाड़ने की नीति बनाई जा रही है।

हम माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहेंगे कि हम दुनिया को अच्छे लगें, यह तो सही है, लेकिन हम वास्तव में भी अच्छे हों, इस देश में कुछ ऐसा इंतजाम करने का कार्य भी करना चाहिए। अगर हम केवल दुनिया को अच्छे लगने के लिए इस देश के 12 करोड़ लोगों को अपरूट करेंगे और उनका कोई सही इंतजाम नहीं करेंगे, तो वह इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने का कार्य होगा और जो एंटी नैशनल लोगों को बहुत बड़ा पोटैंशियल प्रोवाइड करेगा, जिसे वे देश के विरुद्ध भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसलिए हमारा यह कहना है कि housing की जो requirement है उसके accordingly सरकार को बजट में और बढ़ोत्तरी करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि Planning Commission की जो expectations हैं, उनके मुताबिक कोई तैयारी, कोई provision of budget हमें नहीं नजर आ रहा है। आदरणीय मंत्री जी को हमारी यह suggestion है कि कोई ऐसा master plan बनाया जाए जिसमें पहले तो यह identify किया जाए कि हमारे पूरे देश में कितने towns या cities हैं और उनमें कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है तथा झुग्गी-झोंपड़ी में रह रहे हैं। तब उनके लिए एक special master plan बनाया जाए जिससे हम उनको कम-से-कम घर जरूर दे सकें। सरकार आज Food Security Bill लाने की तैयारी कर रही है। मैं समझता हूं कि Food Security Bill लाने से पहले हमारी सरकार को शौचालय सेक्योरिटी बिल लाना चाहिए। शौच के लिए लोग कहां जाएं? हम यह तो कह रहे हैं कि लोग open में न जाएं, लेकिन वे कहां जाएं, उसका कोई विकल्प या उसका कोई समाधान नहीं है। हमारे देश की बदकिस्मती यह है कि हमारे देश में जो लोग नक्सली हो गए हैं उनके आगे हम घुटने टेक रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि आप हथियार फेंको, हम आपको rehabilitate करेंगे। इसी सैशन में रेलवे मिनिस्टर ने बताया कि हमारी 5सौ करोड़ की सम्पत्ति को अभी-अभी उन लोगों ने जलाया है। इस प्रकार इस देश में ऐसी जो movements हैं, उनके लिए तो हम हजारों करोड़ रुपए रख रहे हैं, लेकिन जो लोग ईमानदार और दयानतदार नागरिक बनकर जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास कोई सार्थक या constructive programme नहीं है जिसके कारण हमारा बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए मंत्री जी को हमारी यह सजेशन है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि सरकार एक ऐसा मास्टर प्लान बनाए जिसके माध्यम से सरकार के पास exact figures हों कि हमारे पास कितने बेघर लोग हैं और उनको हम कितने समय में time bound करके घर उपलब्ध करवा सकते हैं। हम यह भार स्टेट्स पर डालते

जाएंगे कि इस काम को स्टेट्स करें, लेकिन स्टेट्स के पास उतने फंड्स नहीं हैं। जब हम स्टेट को फंड देते हैं तो हम बड़ा अहसान जताते हैं। चाहे स्टेट बार-बार डिमांड करे, हम उसकी डिमांड पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब हम स्टेट से लेते हैं तो इसे हम अपना हक समझ कर लेते हैं कि हम देश को चलाते हैं, हमारा संघीय ढांचा है। इस तरह हम स्टेट से लेने के हकदार तो हैं, लेकिन उनको देना अपनी मरजी से है। जहां देना चाहो दो और जहां देना न चाहो नहीं दो। हमारा इसमें यही कहना है कि एक master plan बनाकर इसके लिए एक effective योजना बनाई जाए, ताकि हम उन 12 करोड़ लोगों को भी इस देश में एक आम शहरी की तरह जीने का एक मौका दे सकें।

सर, इसके आगे हमारा जो विषय है, उसमें urban poverty alleviation भी है। शहरों में जो गरीबी या poverty है, उसके लिए हमारे पास क्या प्लान है? हमने यह देखा है कि हमने उनके नाम बड़े अच्छे रखे हैं। मैं उन नामों की चर्चा नहीं करता। हमारे पास जितने गांधी या नेहरु हैं, सब के नाम पर हमने कोई-न-कोई योजना चला रखी है। हर गांधी को हमने गरीबी के खात्मे के लिए आगे लाने की कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हर गांधी के नाम पर चलाई हुई ऐसी स्कीम गरीबी को खत्म करने में नाकाम साबित हुई। हम कहना चाहेंगे कि जो नरेगा है, अब उसका भी नाम बदल गया है, उसके आगे भी अब गांधी जी आ गए हैं। नरेगा का नाम कुछ भी हो, उसमें कमियां हैं। उसके अंतर्गत grassroot पर implementation के लिए और उसके अंतर्गत daily wages पर जो कार्य दिया जाता है तथा उसके बदले में जो दिया जाता है उसमें भी अभी बहुत बड़े सुधार की जरूरत है, परन्तु हम आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि ये योजनाएं शहरों में भी लागू की जाएं। शहरों के जो गरीब हैं, शहरों के जो बेरोजगार हैं, उनके लिए भी ऐसी योजना, चाहे उसके लिए भी आप कोई और गांधी ढूंढ लें या कुछ भी कर लें, लेकिन शहरों के गरीबों के लिए भी कोई-न-कोई ऐसी योजना लागू की जाए जिससे वह वास्तव में अपना जीवन जी सकें।

इसके अलावा, जहां तक अर्बन डेवलपमेंट की बात है, हम शहरों में डेवलपमेंट करते हैं। हमारे देश की सरकार यह कहती है कि हमारे पास ज्यादा आर्थिक-साधन नहीं हैं, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट की प्लानिंग क्या होती है? हम पहले सड़क बनाते हैं और जब एक बार सड़क बन जाती है तो 6 महीने बाद हम उसको दोबारा उखाड़ते हैं। फिर हम उसके नीचे टेलीफोन के तार डालते हैं तो उसकी थोड़ी-बहुत मरम्मत हो जाती है। उसको हम फिर उखाड़ते हैं और उसके नीचे सीवरेज डालते हैं। अब तो यह कहा जाता है कि कुछ शहरों में उसके नीचे चौथी बार बिजली की लाइन भी डालेंगे। ...(**समय की घंटी**)... मैं यह समझता हूं कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, वे भी बड़े मुश्किल से एक बार सड़क बना पाते हैं, हम तो अभी विकासशील कहलाते हैं और हम तीन-तीन, चार-चार बार सड़क बनाते हैं! यह हमारी कैसी दूरदृष्टि है? यह हमारी कैसी अर्बन डेवलपमेंट की प्लानिंग है? हम यह कहना चाहते हैं कि ऐसी प्लानिंग लागू की जाए कि हमें कम से कम एक बार सड़क बनानी पड़े। उससे पहले अगर सीवरेज, टेलीफोन या कहीं बिजली की लाइन डालनी है...

श्री उपसभापति : करीमपुरी जी, अब आप समाप्त कीजिए। यह अर्बन डेवलपमेंट नहीं है, यह अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन है। हम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के ऊपर डिसकस नहीं कर रहे हैं।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : हम अर्बन डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, लेकिन अर्बन पॉवर्टी को डिसकस करते हैं। अर्बन और पॉवर्टी जुड़ा हुआ है।

श्री उपसभापति : यह हाउसिंग और अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन है। ...(**व्यवधान**)...

एक मनानीय सदस्य : नोएडा के स्टेच्यू के बारे में डिसकस करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : नोएडा के स्टेच्यू के बारे में भी डिसकस करेंगे। ...(**व्यवधान**)...

डा. अखिलेश दास गुप्ता (उत्तर प्रदेश) : सर ...(**व्यवधान**)...

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : अगर नेहरू म्यूजियम के कॉस्ट को देखा जाए तो सारे स्टेच्यू उसके बराबर नहीं होंगे, जो आपने उस जगह पर लगा रखे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप सब्जेक्ट पर बोलिए।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : हम यह कहते हैं कि शहर में जो सफाई कर्मचारी हैं, क्या मंत्री जी ने कभी यह अध्ययन कराया है कि ऐसे कितने सफाई कर्मचारी हैं जो सीवरेज में उतरे और फिर वे वापस बाहर नहीं आये? यह पॉवर्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि कम से कम सफाई कर्मचारी को सीवरेज के अंदर न उतरना पड़े। उसके लिए हमें modern equipments available करवाने चाहिए। यह बहुत बड़ी ज्यादती है। यह मानव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है कि हम उसको मजबूर करते हैं कि आप इसके अंदर जाओ और बाहर आओ या न आओ, यह हमारी गारंटी नहीं है।

पॉवर्टी एलिविएशन के लिए हमारा यह कहना है कि आपने किसानों का करीब 70 हजार करोड़ कर्जा माफ किया है। यह बड़ी अच्छी बात है और उस पर हमारा कोई किन्तु-परन्तु नहीं है, अगर आप उसे 80 हजार करोड़ कर दीजिए तो हम आपको appreciate करेंगे। परन्तु, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि जिसके पास जमीन नहीं है, क्या आपने उसके 70 पैसे माफ किये? जब आप वोट मांगते हैं तो आप "हमारा हाथ गरीब का साथ" कहकर डिमंाड करते हैं और बाद में वह हाथ गरीब का खून निचोड़ता है। इसे देश के बजट में गरीब के लिए क्या contributions हैं? जो बीपीएल परिवार हैं, उनको भी आप टैक्स से क्षमा नहीं करते हैं। आप उनसे भी पैसा collect करते हैं, लेकिन वापस उनको नहीं देते हैं। हमारा यह कहना है कि छोटे-छोटे शहरों में रेहड़ी-ठेले वाले जो लोग कार्य करते हैं, वे भी लोन लेते हैं। वे लोन लेकर अपना कार्य चलाते हैं। सरकार को उनका ऋण माफ करने की नीति भी बनानी चाहिए। हमें किसानों को और देना चाहिए, लेकिन जो गरीब अर्बन एरियाज़ में रहते हैं या चाहे वह रूरल एरियाज़ में हों, उनके कर्ज को माफ करने की नीति भी हमें जरूर बनानी चाहिए। शेडयूल्ड कास्ट्स, शेडयूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी के जो लोग हैं, उनके लिए तो स्पेशल प्लान बने।

उनका जो कर्ज़ा है, उसे माफ करने के लिए स्पेशल प्लान होना चाहिए। उनको घर देने के लिए, उनके लिए शौचालयों का इंतजाम करने के लिए ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : करीमपुरी जी, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : अभी तो मेरे बहुत से सजेशंस बाकी हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : देखिए, आपकी पार्टी का alloted time 10 minutes है, चूंकि आप initiator हैं, इसलिए हम आपको 10 मिनट ज्यादा दे रहे हैं। आप सामने स्क्रीन पर देखिए, आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : मैं conclude कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हमारी राज्य सरकार ने Taj Express बनाया है। अब urban development कब होगा? Urban development तब होगा, जब शहरों के नज़दीक एयरपोर्ट होंगे। हमारी राज्य सरकार ने एक एयरपोर्ट की डिमांड की है। यहां दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर एक-एक घंटे तक हवाई जहाज़ घूमते हैं और उसमें हम करोड़ों रुपए का तेल बर्बाद कर देते हैं।

श्री उपसभापति : इसका जवाब मंत्री महोदया नहीं दे सकती हैं।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : वे बेशक जवाब न दें, लेकिन वे इस मामले को Civil Aviation Minister के साथ जरूर उठाएं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : हम लोग यहां जो विषय डिस्कस कर रहे हैं, आप केवल उसके बारे में बात कीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : मैं उसी विषय के बारे में बात कर रहा हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : नहीं, यह poverty alleviation नहीं है ...(**व्यवधान**)...

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : जब शहर विकसित होंगे, तभी poverty alleviation होगा। शहरों को विकसित किए बिना, आप poverty को alleviate नहीं कर सकते। इसलिए मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपसे एयरपोर्ट की डिमांड कर रही है, आदरणीय मंत्री जी, आप हमारी यह डिमांड अवश्य ही Civil Aviation Minister के सामने उठाएं और आदरणीय Prime Minister से request करें कि यह एयरपोर्ट हमें दिया जाए। इसका दिल्ली के डेवलपमेंट में भी बड़ा योगदान होगा और हम इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं ...(**व्यवधान**)... मैं बिल्कुल subject पर ही concentrate कर रहा हूं, क्योंकि overall development ही poverty को खत्म करने का माध्यम बन सकता है। आप poverty को खत्म करने के लिए कोई जंतर-मंतर की पुड़िया नहीं दे सकते हैं कि इसे सुबह-शाम खा लिया करो, इससे तुम्हारी poverty खत्म हो जाएगी। यह दवा तो आप 60-65 सालों से दे रहे हैं। आपकी नीति फेल है। इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि हमारे सजेशंस सुनिए और उनको मानिए। अगर आप इन्हें मानेंगे, तो इस समस्या का कुछ समाधान होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. अखिलेश दास गुप्ता : मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। माननीय शैलजा जी, Urban Poverty Alleviation Minister हैं। Urban poverty तभी दूर होगी, जब इनके पास Urban Development विभाग भी हो। चूंकि दोनों inter-conntected हैं, इसलिए इनके पास additional विभाग भी होना चाहिए।

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation is a very important Ministry. Also, it is a very complicated Ministry. I am happy that we have a very young and dynamic Minister in Kumari Shelja. Immediately after becoming the Minister, she formulated a new policy in 2007 itself. On the basis of that policy many things have been done by UPA-I and UPA-II is also following the same. Sir, I shall quote from a speech made by the President of India in 2009. She said, and I quote, "The scheme for affordable housing through partnership and the scheme for interest subsidy for urban housing would be dovetailed into the Rajiv Gandhi Awas Yojana which would extend support under the JNNURM to States that are willing to assign property rights to people living in slum areas."

"My Government's efforts would be to create a slum-free India in five years through the Rajiv Awas Yojana". It is followed by the speech of the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh on 15th August, 2009. In his Address to the Nation on 15th August, 2009, he said, "We had started the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission for the urban areas. We will accelerate this programme also. Today lakhs of our citizens live in slums, which lack basic amenities. We wish to make our country slum-free, as early as possible. In the next five years, we will provide better housing facilities to slum dwellers through a new Scheme, Rajiv Awas Yojana". These are the focused aspects of the development which are taken by the UPA Government.

Sir, we know very well that the population of India is increasing every minute. Now, we are having a population of 1025 million. Out of that, 28 per cent of the people are living in urban areas. Also, 55 per cent of the total population of the urban areas are living in slum areas. So, today, we are facing such a huge problem. Sir, the migration from rural areas to urban areas had started even before the Independence. But, after the Independence, it started with high hope because the urban areas were developing at a fast rate. Therefore, the people thought that they can go there for better job opportunities. Subsequently, in every Five Year Plan the Government of India has planned

everything properly. Whenever they come forward with any new project, they find it proper that whoever gets the job should have the housing facility also in and around the place where he is working. That was the planning made in the initial stages of the Five Year Plans. And, subsequently, when large numbers of people were coming towards urban areas and slums started to come up, the Government of India started to have various schemes for the low-income groups and the economically weaker groups. So, these are all things which started to work but the degree in which these works were implemented and the degree in which the migration has started towards urban areas is much, much larger which cannot be compensated.

Sir, we have to compare ourselves with China. China had never thought that economy-wise it will have such a huge potential in urban areas, but they thought about it well in advance. I could visit China as a Delegation of the Members of Parliament. We discussed it with the topmost persons who were planning it - the Mayor of Xian City and also at Beijing, Shanghai and everywhere. They constructed buildings with 100 floors, 120 floors and 200 floors. They openly said, "We allow the rural area people to come to urban areas, and we allow them to have the skill development. Millions of people are needed for urban development, for laying roads, for making bridges, for putting new railway stations, and putting airports, etc. Therefore, we are allowing them to come out. We are wooing them towards urban areas. Similarly, we are also giving them minimum facility of owning a house as a proud property of them." This is the Chinese aspect. But, they have faced this situation only in the last 10 years. We started our own programme in a much planned way, and we allowed the slums being properly looked after and the basic necessities are provided there. But, at the same time, what happened is this. The implementing agencies have to have the dynamism to do it within a particular period. The Government of India is pumping money every year, but it has to be executed by the State Governments, more so, by all the Nagarpalika system which was initiated by Rajiv Gandhiji. He amended the Constitution to give more rights to urban areas. Now, the Nagarpalika system is being followed.

(THE VICE-CHAIRMAN, **PROF. P.J. KURIEN** in the Chair)

So, now they can decide in which way they can remove the slums. They can build up new houses. They can make the people happy by having better water facilities, sewage system, roads, schools, medical facilities, etc. So, everything can be planned by the Nagarpalika system.

And the Constitution also is allowing it as a third tier of the system of governance. But, unfortunately, everywhere the Nagarpalika system is failing because of non-participation of the civil

society as also the people who are elected to that system. They feel that it is not their work, that it is the work of somebody and that the Government gives money and they only have to spend it through contractors. Hence, they are not worried about it. Ten years after constructing a huge housing scheme, it becomes unusable. This is happening in every city. Therefore, it is high time to create an awareness among the elected representatives and the civil societies that it is the taxpayers' money that is spent for a purpose and that we need to participate in that and protect the public assets which are created by the taxpayers' money. Therefore, Sir, if that aspect is built in them, then very clearly we can say that the President of India's address is very focused. She clearly told that the creation of assets is the main thing, on which we are working. I am just quoting what she said, "To assign the property rights to the people living in slum areas..." This aspect can be implemented only by a very dynamic Nagarpalika system. They have to have a better coordination with the State Governments, they have to find out the land availability; if the land availability is very low, then they have to go in for skyscrapers and give all the facilities in it. Such facilities are available in big private sector housing schemes. Now, 10,000 or 20,000 houses are constructed in one new colony, yet they are giving all facilities in that. At the same time, when the urban development scheme is done through an agency of the Government, we will find that a totally different quality is given by all contractors.

Therefore, Sir, it is high time to see to it that the people who are the beneficiaries also have a participation in all the schemes. Now, we are giving excellent schemes to the public. We are not only giving houses but also providing employment opportunities. If a person wants to have self-employment, we are giving an aid to the extent of Rs.2 lakh with a very, very minimum rate of interest; moreover, when the UPA came to power, the subsidy amount has been increased from Rs.25,000 to 50,000 to the self-employed people. There are many self-employed people. They are utilizing that amount.

Similarly, we are giving a lot of schemes in the name of skill development. We are allowing them to acquire skill even though they pass out just eighth standard or tenth standard examination. They can choose from the available skills for a suitable job. The Government of India is offering various schemes to every section of the people like the Scheduled Castes, to the weaker sections of the society.

Moreover, after the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh came to power, Soniaji has given avenues to every section. The minorities are also focused. The minorities are given more importance.

Wherever their population is concentrated, they are given importance. Even in the Budget it was announced that wherever there is a concentration of minority population a nationalized bank branch would be opened for them, exclusively for the minorities. Such are the schemes the Government is offering. But, how much are they being utilized? We must ask ourselves: Are we focusing on the dissemination of the availability of schemes offered by the Government of India? Similarly, Sir, there are other schemes coming up, like the self-help groups. Huge number of female workers is available.

Sir, you know very well that earlier the rural folk used to come with their entire family members when the off-season started. After the harvest was over, they used to come in large numbers - with small children in their arms; the number may be 20, 30 or even 100. They used to come to the urban areas. They did not have any facilities for their living. They used to come depending solely on their legs and arms. They were having only the physical stamina to work. We have many laws in order to protect and take care of them. But, how are they implemented? How is the Nagarpalika system coordinating in that effort? They are coming only for the wage-earning.

They feel that within that three months period of off-season, they can earn Rs.5000 or Rs.10000 as a bulk amount so that when they go back, they can start their agricultural work. That is the attitude with which they come to the urban areas. Fortunately, Sir, even though we are having so many schemes in the last three Five Year Plans giving guarantee to the people in the rural areas that they will be assured of their income, but none of the things could be done properly because the Executive was having so much of power to see that what type of work to be given and to whom it should be given. Madam Soniaji has made it possible by making the UPA Government to enact a law guaranteeing the rural poor of getting job, assured job and the amount has been increased from Rs.80 to Rs.100. In certain States, they are giving even more, Rs.150. It is because of this reason that the rural population is withholding itself from migrating to the urban areas. That is one of the best strategies that we are following in India because most of the people who are coming to the urban areas, they are in search of jobs. So, the first aspect is like that. Another thing is that we are having a joint family system even in the villages. Though the joint family system in the middle and upper middle

classes is broken, but at the lower level even now they are having joint family system. Therefore, when they migrate from one place to another, they move with a feeling that they should take even elderly people and children also with them because they have to be protected. That type of attitude is there among the Indians, more so among the rural Indians. So, they are coming with entire family to the urban areas. Then the problems start because old people have to be looked after, their health is to be looked after, they may not have the potentiality of getting employment and other things, children may not have access to the education, etc. Fortunately, the UPA Government has come forward that both to the rural and urban poor, wherever it is possible, a Fundamental Right is given for education. They can also join the best schools if they show the merit. In such a situation, Sir, the UPA Government is also having a comprehensive programme of giving health insurance to these poor people. If they are paying Re.1 per day for one year, Rs.200 will be subsidised by the Central Government and this amount is sufficient to get a health insurance of Rs.35000. If the same people give more, then, automatically, they are given health protection insurance of Rs.1 lakh. Many of the States are coming forward and I can give the example of Andhra Pradesh. When Y.S. Rajasekhara was the Chief Minister, he launched pioneer programmes in various sectors of urban areas. When the Government of India proposed that the housing scheme needs to be implemented and proposed that 80 per cent will be given by the Central Government and 20 per cent will be the participation of the State Government, many of the States even could not afford to pay that 20 per cent. But YSRji did it. He made Indiraamma Housing Scheme. You can see mighty buildings in the urban areas of Andhra Pradesh. They have given the scheme of Arogyashri '108'. For the past four years they have been having this health scheme. Wherever they are, if they just phone up, an ambulance would come and they will be admitted in one of the high level, sophisticated hospitals and super speciality facilities will be given even to a small man in the urban area or rural area. Therefore, their budget is of more than Rs.1500 crores which they have to spend. They are actually helping the ordinary people. For four or five years, it has been in operation. Now the Tamil Nadu Government is also following this example. They are having their own system of health insurance scheme. They are coming with an insurance of Rs.1 lakh while the Andhra Government is coming forward with an insurance of Rs.2 lakh. In Tamil Nadu, they have certain proposition with regard to certain diseases which are covered which is something different form Andhra Pradesh. I could find it when I made a study on this subject. Similarly, with regard to housing scheme, the Central Government is giving money. The Government

of Tamil Nadu is using it properly and in the urban area they have Periyar Housing Scheme where all types of people can live together without any caste or religious discrimination.

Similarly, I find they have done a lot of schemes like that in Andhra Pradesh for the past five years. Sir, these are the examples which show that if the State Government has got a will to do and the urban elected body has the will to do, they can achieve it. We can find out how much they are spending every year for habitation alone from the target which was made in China. Chinese real estate development was started in 1999. They are spending 48.43 billion US dollars. Similarly, they are now having 480 to 549 million square metres of built up area. They are having 5.23 billion to 5.91 billion square feet of new residential houses. Similarly, India is also having its own projection. They have got their own better habitat with million plus cities. Now, within 20 years, India has come to 26.8 per cent cities which are having more population. By 2001-2035, they feel the projection will be 37 per cent. Urban area employment generation will be increased to 19.3 million and rural population will have five million employment opportunities. The female workers' ratio is now increasing in India. Similarly, Sir, we can very well say that we have got very clear plan of how economically weaker sections can be helped. According to the 61st Round of NSSO calculations, we are going to have 4.4 million people under the economically weaker sections who need affordable housing schemes and LIG scheme will also be implemented by the Government of India. The urban population is now classified as: if 5000 persons are living within a particular one square kilometre or 400 persons are living, then they are classified as urban area. Therefore, plenty of urban areas are coming up, but, infrastructure needs to be compensated by proper planning at the State level. But the UN-HABITAT has got a projection that the adult population has to be looked after. Every calculation was made only in 2001 census. Subsequently, we have passed through ten years. Lots of changes have come up. With regards to economic growth, we are going through a super-sonic speed. Many of the people are coming to urban areas. Upper middle class level people who have been educated, graduated, master degree holders, technically educated people are coming towards urban areas. The lower strata of people are looked after by the Employment Guarantee Scheme. Many of the schemes are given to the rural areas. But, the rural areas need the scale of development for employment opportunities by having more industries, more industrial ventures, more of the software parks put up in the rural areas. Allowing it to mushroom within the urban areas will not help the scale of

development. Therefore, the holistic pattern of development has to be looked after. I am very happy, Sir, that the Ministry is working very well. Very dynamic Minister will have many more programmes in future but the coordination between the State Government and the *Nagar Palika* system is much more needed with the civil society's appreciation of it.

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा प्रारम्भ हुई है। सुदर्शन जी कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे और उन्होंने सात बार गांधी परिवार का नाम लिया। एक व्यापारी थे और उस व्यापारी के घर 12 बच्चे थे, तो उसके छोटे बच्चे का नाम राम-राम था। मैंने उससे पूछा कि तुमने इस बच्चे का नाम राम-राम क्यों रखा है। उसने कहा कि दिन भर भगवान का नाम नहीं ले पाता हूं, क्या करूं, इसलिए इसको जितनी बार बुला लेता हूं - राम-राम इधर आओ, राम-राम पानी लाओ, राम-राम इधर बैठो, उतनी बार भगवान का नाम ले लेता हूं। ऐसे ही यह आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का मुख्य काम हो गया है योजनाओं का नाम राजीव गांधी, अन्य लोगों के नाम से, गांधी परिवार के नाम से रखो - वैसे तो उनको याद नहीं कर सकते, लेकिन इसी बहाने राम-राम की तरह इन्हें याद करो। मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा उपयोग उनका है। ...(**व्यवधान**)... मुझे लगता है कि 50 वर्षों तक यह मंत्रालय अब समाप्त होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि देश की आबादी और देश की गरीबी तथा देश में आवास की कमी निरंतर बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि शैलजा जी बदल जाएं, अन्य मंत्री आ जाएं, अन्य सरकार आ जाए, लेकिन यह मंत्रालय रहेगा, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से और राष्ट्रपति के अभिभाषण में असत्य जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, वह देश के साथ * की जाती है। 1952 से लेकर 2009 तक प्रधान मंत्री के भाषणों को देख लीजिए, चाहे जो प्रधान मंत्री रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इस भारत को तो अमेरिका हो जाना चाहिए था। सुदर्शन जी कह रहे थे कि मैं चीन गया था और वहां के मेयर से बात की, उन्होंने ऐसा-ऐसा कहा। आप भारत के किसी शहर के मेयर से तो बात कर लीजिए। उसकी क्या हालत है? वह अपने नगरपालिका के कर्मचारियों को वेतन नहीं बांट पाता है। आपने 74वें संशोधन में उन्हें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, उसके बाद भी ये सब बातें नहीं हो सकी हैं। अब बात आती है कि आप 1971 से नारा दे रहे हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हटी है? आपको मंत्रालय बनाना पड़ा है। आप * किससे करते हैं, आम आदमी का हाथ, गरीबों के साथ, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, ये नारे आपके हैं, अपने ही घोषणा पत्र के साथ आपका जो यह * है, यह आपको माफ नहीं करेगा। आप हमेशा * करते हैं। ...(**व्यवधान**)... मनुष्य की आवश्यकता होती है, जिंदगी में हर आदमी एक सपना देखता है कि उसके पास एक घर हो और उसका जीवन गरीबी से मुक्त हो। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, लेकिन आंकड़ों की जुगाली से ही यह नहीं चलेगा, इसके लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। हमारी तीन मूल-भूत आवश्यकताएं

*Expunged as ordered by the Chair.

होती हैं - रोटी, कपड़ा और मकान। मकान की स्थिति क्या है, यह हम सब जानते हैं। अभी सुदर्शन जी कह रहे थे कि पलायन होना चाहिए। गांव खाली हो जाएंगे, तो आपके खेत को कौन संभालेगा? कृषि पर आधारित भारत की अर्थ-व्यवस्था है, अगर कांग्रेस के लोग यह कहते हैं कि पलायन ठीक हे, यह होना चाहिए, डेवलेपमेंट के कारण उनको आना चाहिए। शहर की गरीबी का मुख्य कारण है कि आपने प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी है, चकाचौंध पैदा कर दी है, उसको देखकर गांव का आदमी सोचता है कि क्यों न वह गांव से शहर अपने पेट को भरने के लिए जाए और गांव को छोड़ देता है। गांव छोड़ने का मतलब संस्कृति छोड़ना है। गांव एक संस्कृति होती है, गांव कोई सामान्य चीज़ नहीं होती है और आप पलायन की हमदर्दी दिखा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पलायन नहीं होना चाहिए। शहरी गरीबी का मुख्य कारण पलायन है, जो गांव से लोग आते हैं, वे क्या-क्या नहीं करते हैं, उन्हें नालों के किनारे रहना पड़ता है। आप ट्रेन से चलते होंगे, क्या हालत रेलवे की है, पटरियों के किनारे आवास मंत्रालय देखा जा सकता है, वे खुली छत के नीचे कैसे रहते हैं। हम कितना असत्य बोलेंगे और कितना असत्य बोलते रहेंगे।

हर शहर में एक चौथाई स्लम पाया जाता है और स्लम की हालत क्या है, जरा जाकर देखिए। अगर एक बच्चा छोटी "अ" पर कुछ नहीं, बड़ी "आ" पर लठिया पढ़ रहा होगा, तो दूसरे के कमरे में आवाज जाएगी। हम स्लम की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में लिखा है मुक्त, झुग्गी मुक्त। आप मुक्त हो जाएंगे, जनता आपको मुक्त कर देगी, आप झुग्गी मुक्त नहीं कर सकेंगे। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? वहां पर शौचालय की क्या स्थिति है, वहां पर शिक्षा की क्या स्थिति है, वहां स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, आपकी योजनाओं की क्या स्थिति है, वहां जाकर थोड़ा देखिए, तो सही। आपके कितने मंत्री स्लम एरिया में जाते हैं? क्या आप स्लम एरिया में देखने जाते हैं कि वहां पर लोगों की क्या स्थिति है? वहां पर गटर का पानी बह रहा है, नाले में कीड़े चल रहे हैं, वहां आपका आवास मंत्रालय रहता है, भारत का नागरिक रहता है और उस नागरिक को वही अधिकार है, जो एक वोट देकर आपकी सरकार बनाता है, एक वोट वह भी देता है, लेकिन उसकी नरकीय जिंदगी के प्रति इस सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। शैलजा जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, जो आपने 2009 में शहरी गरीबों की रिपोर्ट दी है, उसमें बताया गया है कि 25 मिलियन आवास की आज भी भारत को जरूरत है, दो करोड़ 65 लाख मकानों की आवश्यकता है। आप इतने मकान कैसे बनायेंगे, आपके पास इसकी क्या योजना है? आपने घोषणा की थी, जैसे ही चुनाव आता है, तो इनके नारे सुनिए। शैलजा जी ने कितने बयान दिए हैं, शहरी गरीबों के लिए पांच लाख मकान बनाये जायेंगे, यह 2009 के चुनाव के तीन महीने पहले कहा। राजीव गांधी योजना में तीन साल में 25 लाख मकान बनाए जाएंगे, उनमें से कितने बने, आप बता दीजिए। भारत को झुग्गी मुक्त करने के लिए 25 लाख मकान बनाए जाएंगे, यह सब मैंने अखबारों से लिया है। सभी गरीबों को मकान के लिए कम दाम पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, मकान बनाना आसान होगा, ये लाखों, करोड़ों लोग झुग्गी और स्लम्स में क्यों रहते हैं, आप चुनाव के समय 2014 में ये कोरे वायदे फिर करेंगे। आपके पास जमीन नहीं है, मुझे लगता है कि आपको लोगों को इस नारकीय

जिंदगी से उबारने के बारे में उपाय सोचने चाहिए। आपकी भौगोलिक स्थिति क्या है? देश के शहरी क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र हैं 2.3 प्रतिशत, जबकि वर्तमान में इस क्षेत्र में देश की कुल आबादी का 30 फीसदी रहता है। देश की कुल आबादी 30 फीसदी कहां रहती है। 2.3 प्रतिशत क्षेत्र में। शहरी गरीबी की स्थिति क्या है, आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, वे सभी फेल हो रही हैं। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की एक रिपोर्ट 2009 की है। उसमें लिखा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 28.5 करोड़ लोग रहते हैं। यह इस देश की कुल आबादी का 27.6 फीसदी आंकड़ा है। इस बढ़ोत्तरी की वर्तमान दर को देखते हुए 2030 में यह 57.5 प्रतिशत हो जाएगा और 57.5 फीसदी लोग शहरी गरीबी के क्षेत्र में रहने लगेंगे। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अपितु आपकी जनगणना के आधार पर कह रहा हूं। मैंने यह भी बताया कि दो करोड़ 65 लाख मकान चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। महाराष्ट्र के महार क्षेत्र में 3865 फ्लैट्स के लिए एक विज्ञापन निकला। उसके अनुसार सौ रुपए देकर फार्म ले लीजिए। उन 3865 फलैट्स के लिए 100 रुपए देने वाले लोगों की कितनी संख्या है? पांच लाख फार्म खत्म हो गए और सरकार ने पांच करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए तथा और पांच लाख फार्म छाप दिए। मकान देने हैं 3865 लोगों को और फार्म भरवा लिए पांच लाख लोगों से तथा और पांच लाख फार्म छाप दिए! आप पांच लाख फार्म और बेचकर, दस करोड़ तो ले ही लेंगे। आपको इस आंकड़े से अंदाजा लग सकता है कि इस देश में आवास की क्या स्थिति है? 3865 फ्लैट्स के लिए, दस लाख आवेदकों की लाइन में सौ रुपए देकर, एक दिन की ड्यूटी की नागा करके, लोग फार्म भरते हैं। यह आपके आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की हालत है। यह आपकी महाराष्ट्र की रिपोर्ट है, जिसको मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। एक सरकारी संगठन है, centre on housing rights and evictions. उसकी रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। उसने कहा है कि इस देश में धनाभाव के चलते करीब 15 करोड़ लोगों के सिर पर आवास चाहिए। यह सरकारी सर्वे करने वाली एजेंसी नहीं है, प्राइवेट एजेंसी है। यदि टूटे-फूटे सब मकान जोड़ लें, तो 15 करोड़ शहरी लोगों के सिर पर मकान नहीं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे उनकी रात बीतती होगी, बरसात में क्या हालत होती होगी, ठंड में क्या हालत होती रहेगी और गर्मियों में क्या हालत होती होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आपने कई योजनाओं की बात कही है कि राज्य कुछ नहीं करते हैं। नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन NSHO ने भी कहा है कि 32 फीसदी भारतीय शहरियों के लिए आज आवास नहीं हैं। आगे देखिए, 17 करोड़ लोग झुग्गियों में रहते हैं। यह आपकी रिपोर्ट है। आप उनकी स्थिति की कल्पना करिए कि उनकी क्या स्थिति है, कैसे रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने उनके लिए शौचालय की कोई व्यवस्था की है? क्या उनके बच्चों के लिए पढ़ने-लिखने की व्यवस्था की है? जो सामान्य सुविधाएं होती हैं और जो हमें संविधान में एक सामान्य नागरिक के नाते दी गई है, क्या वहां पर उन सुविधाओं की व्यवस्था है? क्या राशन की दुकान है, केरोसीन की दुकान है, क्या गैस की एजेंसी है? वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां पर कोई नागरिक सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप कह रहे हैं कि सिविक सेंस डेवलेप होनी चाहिए। यह सिविक सेंस तो 15 अगस्त के बाद से ही होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने वोटर सेंस तो डेवलेप की, लेकिन हमने इस देश में कभी

सिविक सेंस डेवलेप नहीं की। कोई कहता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको पांच ग्राम सोना देंगे। कोई कहता है कि हम रंगीन टेलीविजन देंगे, आप हमें वोट दीजिए। अगर आप सिविक सेंस डेवलेप करते, तो शायद यह बातें नहीं होतीं। आपने 60 वर्षों में सिर्फ वोटर सेंस डेवलेप की है और वोटर सेंस के नाते ये झुग्गियां बढ़ रही हैं, क्योंकि आप वोटर को लोभ से जोड़ते हैं, राष्ट्र से नहीं जोड़ते हैं। आप अपने लोगों से विचार कर लीजिए। आप अपने नारों और घोषाणओं के कारण उन्हें मंत्रमुग्ध करते हो और धोखा देते हो। इसलिए मुझे लगता है कि लगातार जो यह क्रम चला है, यह भारत के लिए नहीं, हम सबके लिए है। हवाई जहाज से कोई विदेशी उतरकर क्या देखता है? सांताक्रुज का स्लम्स देखता है। सबसे पहले देखता है, वह कैसे रहेगा? उसके मन में वही एक भाव आता है कि भारत एक गरीब देश है। उसके मन में भारत के प्रति भाव नहीं होता है। आप कहते हैं कि हम इक्कीसवीं सदी में चले जाएंगे, हम यह बनाएंगे, हम सुपरसोनिक हो रहे हैं। आपको कहने से कौन रोकता है, लेकिन इसकी असलियत क्या है? आप इन 17 करोड़ परिवारों में झांककर देखिए, अपने सभी मंत्रियों को भेजिए, हम सभी सांसदों का नैतिक कर्तव्य है, मैं यह बात पार्टी से ऊपर उठकर कह रहा हूं, उनकी जिंदगी देखिए - कोई स्वास्थ्य के अभाव में मर जाता है, कोई दवाई के अभाव में मर जाता है, उनके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, वे रोटी नहीं खा पाते हैं, उन लोगों की चावल की माढ़ी पीकर अपने बच्चों को पालने की स्थिति है। यह आपका आवास मंत्रालय है, आपकी गरीबी है, आप इसको देख सकती हैं। आज 52,000 मलिन बस्तियां हैं। अगर इन मलिन बस्तियों का नाम आपसे पूछें, आपके प्रतिनिधि को पता होगा, आपके कॉर्पोरेटर को पता होगा, लेकिन क्या स्थिति है? अगर बिजली का बिल नहीं भरा तो लाइन कट गई। अब पूछिए कि बिजली लगी कैसे? वहां पर बिजली कैसे लगी? गलत तार, गलत लाइन कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहां पर दादागिरी चलती है। वहीं से बहुत सारे गुण्डे पैदा होते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अगरआप उनको नरकीय जिंदगी से बाहर निकालेंगे, तो शायद वे सभ्रांत नागरिक बनेंगे, लेकिन होता यह कि गरीबी उन्हें चोर बनाती है, गरीबी उन्हें उचक्का बनाती है, गरीबी उन्हें चेन खींचने वाला बनाती है, गरीबी उन्हें लुटेरा बनाती है और इसके लिए कहीं न कहीं हम सभी लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, खास कर के जब आप पर जिम्मेदारी है, आपकी सरकार है, तो मैं यह सिर्फ बुराई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको सारी स्थिति बता रहा हूं कि आपकी गरीबी की क्या स्थिति है। आप कौन-कौन सी योजनाएं चला रही हैं? आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या दे रही हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी योजनाओं की क्या स्थिति है। "जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन" के तहत अनुमोदित परियोजनाओं में जो केंद्रीय राशि अनुमोदित की गई थी, उसे चार किस्तों में स्वीकृत किया गया था। प्रत्येक किस्त में पच्चीस फीसदी अंश देना था। यह प्रत्येक सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देना था, लेकिन सरकार कितनी गंभीर है, इसका खुलासा केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा 25 फरवरी, 2010 को राज्य सभा के एक प्रश्न में दिए गए उत्तर से होता है। मंत्रालय ने प्रश्न के जवाब में इस बात का खुलासा किया है कि "जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन" के तहत अनुमोदित परियोनाओं हेतु जो अंश या राशि अनुमोदित की गई थी, उसमें केवल प्रथम किस्त में सभी राज्यों हेतु राशि स्वीकृत की गई है। इसमें केवल कुछ राज्यों हेतु राशि एक दो किस्तों में दी गई है। वे दो राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और गुजरात में केवल चार किस्तों में राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन इन दोनों राज्यों को कुल अनुमोदित केंद्रीय राशि और अब तक स्वीकृत चार किस्तों में काफी अंतर है। आंध्र प्रदेश को 1,497.42 करोड़ रुपए की केंद्रीय राशि अनुमोदित हुई, परंतु चार किस्तों में राशि अनुमोदित होने के बावजूद उनको मात्र 673.92 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। जहां तक गुजरात राज्य का प्रश्न है, गुजरात को 691.74 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित

की गई थी और उन्हें चार किस्तों में 402.02 करोड़ रुपए दिए गए। यह "जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन" की आपकी रिपोर्ट की कहानी है। मध्य प्रदेश को कुल 344.20 करोड़ की केंद्रीय राशि अनुमोदित की गई थी और अब तक तीन किस्तों में, जो राशि स्वीकृत की गई है, वह 117.29 करोड़ रुपए है। हम यह बताना चाहते हैं कि आपने छत्तीसगढ़ के साथ भी बहुत भेदभाव का व्यवहार किया है। छत्तीसगढ़ राज्य को इस परियोजना हेतु कुल 335.23 करोड़ केंद्रीय राशि अनुमोदित की गई थी, परंतु राज्य को अभी तक केवल एक किस्त स्वीकृत की गई है, उसे 83.80 करोड़ की राशि दी गई है। आप राज्यों के साथ कितना भेदभाव करते हैं। हम संघीय प्रणाली में जीते हैं, यहां फेडरल सिस्टम है और इसमें कहीं पर भी, किसी भी पार्टी की सरकार हो सकती है, लेकिन ये आपके आंकड़े हैं, आपके मंत्रालय के आंकड़े हैं और ये बताते हैं कि जहां पर आपकी सरकार नहीं है, वहां पर आप कैसा भेदभाव करती हैं। एक ही आवास एवं विकास कार्यक्रम के संदर्भ में मंत्रालय ने आश्चर्यजनक खुलासा किया है। इस परियोजना हेतु जो केंद्रीय राशि अनुमोदित की गई है, उसे दो किस्तों में स्वीकृत किया जाना था, प्रत्येक किस्त में पचास फीसदी पैसे देने थे, लेकिन अभी तक केवल सात राज्यों को दो किस्तों में राशि स्वीकृत की गई है, शेष राज्यों को अभी एक किस्त दी गई है। यह आपके स्वयं के प्रति आपके मंत्रालय का कैसा रुझान है, यह आपके आंकड़े ही कह रहे हैं। मध्य प्रदेश ...(**व्यवधान**)...

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी शैलजा) : राज्य काम करें और पैसा ले लें। मैं जवाब तो दूंगी, लेकिन जहां तक यह छोटी सी बात है, मैं शॉर्ट प्वाइंट पर कहना चाहूंगी कि हम इंतजार करते हैं कि राज्य सरकारें पैसा खर्च करें। यह एक ऐसा मंत्रालय है, जो राज्यों के पीछे भागता है कि आप हमसे पैसा लीजिए। वे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दें, हमसे पैसा लें, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। In Andhra Pradesh, there is Congress Government and in Gujarat, there is BJP Government. यहां भेदभाव नज़र नहीं आ रहा है ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रभात झा : मैं यह कह रहा हूं कि ये आपके आंकड़े हैं। आप पैसा क्यों नहीं दे रही हैं, वे क्यों नहीं ले रहे हैं, यह आप जानें, मैंने तो मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा की है। आपने बहुत साफ कहा है। आप उनके पीछे लगे रहिए, यह आपकी duty है। लेकिन आपको उनसे certificate लेना है, आप सबसे certificate लेती हैं, क्या आपने आन्ध्र प्रदेश से certificate लिया है? मध्य प्रदेश के एकीकृत आवास एवं श्रम विकास कार्यक्रम के तहत कुल 192 करोड़ रुपए की केन्द्रीय राशि अनुमोदित की गई थी, परन्तु दो किश्तों में केन्द्रीय राशि की स्वीकृति दी गई। सर, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। देखिए, गरीबों को सपना दिखाना बहुत आसान काम होता है। अगर यह हम पर और आप पर बीती होती और यह नारकीय जीवन हम और आप जीते, तो शायद समझते कि गरीबी क्या होती है और आवास के बिना जीने वाले लोगों की स्थिति क्या होती है।

मैं दो लाइनें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा और कहूंगा कि ठीक करिए, अच्छा करिए।

"महल बनाने वाले अक्सर फुटपाथों पर सोते देखे"

-- और जो आप कह रही हैं कि रिपोर्ट दें और पैसा लें --

"सत्य कथाओं के पन्नों पर सारे किस्से झूठे देखे।"

आपके सारे किस्से असत्य हैं, आप चाहे जितनी बातें कर लें, चाहे जितने आंकड़े प्रस्तुत कर लें। धन्यवाद।

SHRI K.N. BALAGOPAL (Kerala): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak in this august House. This is the first time that I am speaking in this House and being my maiden speech, I hope, the much experienced stalwarts who are sitting here and hearing me will pardon me or forgive me for the mistakes that I may make in my speech due to my inexperience.

Sir, the subject of urban poverty alleviation and housing, which we are debating today, is a very important subject. A discussion on housing as well as poverty alleviation gives us a good opportunity to speak and go into the details of the callous attitude which the Central Government is having towards the common people of this country.

Sir, urbanization, as other speakers have already spoken, is a very serious situation at present and if you look into the UNDP report of 2009, the focal area of discussion in that report was urbanization. The focal subject is 'Overcoming Barriers - Human Mobility and Development.' In that report, it has been said that every year more than 5 million people are going to the developed countries for employment and the Report says that in the developing or developed countries, this urbanization number and its percentage is quite high. In the replies which have been given in the Parliament itself, it has been said that the urbanization in the country is also alarmingly going up and now 27.8 per cent of the population is living in urban areas; and by 2050, 45 per cent of the population will be in the urban areas. If you numerically look into this matter, in 2011, it will be 32 crores and in 2021, it will be 53 crores. Sir, the hon. Minister, Kumari Selja, has replied in her statement in the Lok Sabha that a Technical Group Study assessed that by the end of the 10th Five Year Plan, there will be a shortage of 24.7 million houses in the urban area. It means, this shortage will only be in the urban areas. It shows that there is a huge shortage in the country which is to be tackled. Report on the Urban Development Ministry says that under JNNURM scheme, near about 1.09 million houses are sanctioned which will be completed in the next 5 to 7 years. Sir, it will not meet even 10 per cent of the necessity. It is less than even 5 per cent of the necessity. If we will go at this speed, I think, it will take, at least, 100 years to provide housing in the urban areas. This is the situation only in regard to the urban housing. We are not looking into the situation that is prevailing in the rural housing. So, the situation is very serious in the urban sector. Sir, we have a lot of

programmes under JNNURM, BSUP, IHSDP, RAY, etc. Many Schemes are there. But in the given situation, the problem of housing is not addressed well. The Planning Commission has also made an observation in this regard. A Planning Commission Member is also here as a new nominated Member of the Rajya Sabha.

They observed that out of ten houses in the country, if one house is built for High Income Group, two houses must be built for Middle Income groups, three for Lower Income Group and four for the economically weaker sections. Now, the economically weaker sections are very important, but Government needs to pay more attention to the Lower Income Group and Middle Income Group too. At present, only High Income Groups are being taken care of. The situation is quite bad. There are schemes for High Income Groups and real estate business take care only of the High Income Group, but something needs to be done for the Lower and Middle Income Groups as well. There is the National Urban Housing Policy of 2007, but it is not legally enforceable; it is only a policy. There should be a policy that empowers people and Governments to do something for the Middle and Lower Income Groups. A regulatory mechanism to be established through legislation.

Sir, there are many schemes under the JNNURM. I had discussions with some Government Secretaries and some Mayors of Corporations from Kerala. The problem with JNNURM is that it is limited only to a few cities. There is provision for housing but there is a ceiling for spending. Four hundred crores is the ceiling limit for Kerala. In the two cities of Trivandrum and Kochin, a maximum of 400 crores is allowed for housing. Officials of the Government say that they have projects and they wanted more money but the Central Government is not giving it. That ceiling should be lifted and funds should be given. Another problem in JNNURM, they say, is that as per the Central Government regulations, there is no scope for flexibility. There is no provision for acquisition of land. Without money for acquisition of land, how could a panchayat or municipal corporation in an urban area get land? That is one problem. The other problem that most of the areas are facing is the escalation of costs. There is no provision for tender rescue. So, this also needs to be addressed.

Sir, I have been trying to deliver my maiden speech for the last three-four days but because of disruptions over IPL and other issues, that did not happen. Just like in IPL and in other areas, even in housing sector there is the real estate mafia. Land is a better option to put in any amount of money. Just like there is hoarding in foodgrains, there is hoarding in land too. There should be some regulatory mechanism to give some power to the Governments to stop such hoarding of land. Can

the employees of Parliament, the journalists middle level officers in the Government other than the rich think of purchasing a piece of land in Delhi? Can they build a house in Delhi? Can they build a house in other metropolitan cities or even two and three-tier cities? It is not possible as prices have skyrocketed in the area of housing. One may need even one crore rupees or more for building or purchasing houses in some parts of the city and even on the outskirts of Delhi. This needs to be checked.

The Budget has provided for very less allocation for housing. The Minister is quite dynamic. I know her personally. I was Political Secretary to the Chief Minister of Kerala and I visited her with the hon. Chief Minister. She is very pro-active and full of ideas. But, in the given situation, the allocation for housing in the Budget is very less. We say in Malayalam 'Kadalil Kayam Kalakkiyathu Pole' (like mixing Kayam in ocean.) 'Kayam' is sambar masala. It is good if we use sambar masala in the sambar but if we put sambar masala in the ocean, what would be the result? So, the funds available with the Ministry are very less. Even though the Minister is active, it is the policy of the Government which is creating a problem.

In China, people are invited to the urban cities for jobs. What is happening here? People are thrown away from villages because of the failure of agriculture, because of the failure of our basic industries and because of the failure of traditional industries. In China, they are invited for employment but here they are thrown away because of the globalization problem. I proudly say that I am coming from Kerala where we have the experience of Total Housing schemes. Earlier there was lakh houses scheme and then through People's Planning Programme lakhs of houses were built. Now, present LDF Government has started EMS Housing Programme. In that Programme, almost all houseless people will get houses within two years. It means that we are planning five to seven lakhs houses. It is for the information of the Minister that we are providing land also for building house to the land less. Government will give Rs.80,000 for purchasing land to those who are staying in urban cities and Rs.45,000 to those who are living in villages. Panchayats or Municipalities through their plan give land price plans house building cost from their plan fund and through borrowing and the Government give interest on loan. This kind of pro-people steps are happening. In Bengal also. There is a new scheme for giving land to landless refugees. In Tripura, also housing schemes are theire. So, such experience is possible in other parts of the country. That is possible and that is why

4.00 **P.M.**

we are saying about this. Sir, a new problem is there in the housing sector. It is the lack of availability of building materials and the sky rocketing cost of building materials. In Kerala, we are importing sand from Rajasthan and Gujarat because we don't have sands. Can you believe that? Environmental laws also restrict us. So, we are importing it. One truckful of sand costs usmore than Rs.5000. This is the situation. There is a research wing in the housing sector under the Government. But no serious research is going on there. Low cost building material is an important and it is to be made available. Sir, there is a new scheme, namely Rajiv Gandhi Awas Yojana for interest subsidy. In this scheme, Central Government spent only Rs.36 lakh for interest subsidy last year. Only Rs.36 lakh for interest subsidy in such a large country! It shows the failure of the scheme. ...*(Interruptions)*... In the area of poverty alleviation, we are saying about urban poverty alleviation only. Here also, we need some honest approach. Why is there poverty? There are many reasons for this. People are coming to urban cities for livelihood. When they live in villages, they have some social system. When they come to urban places, poverty is one of the very serious problems for them which is different from that of the village. One thing we have to ensure in cities is employment. In Delhi, people come from far away places. If you go to Noida, you can see slogans for 'minimum wages'. हमें minimum wages देना चाहिए। Such slogans are there. But in Delhi minimum wages are not implemented in many areas. How people can live there with minimum earning of Rs.2000 or Rs.3000? This is the situation. So, one thing that we have to ensure is minimum wages.

I think, basic facilities for urban infrastructure also come under poverty alleviation. You have to provide better transport facilities; you have to provide food, water, sanitation and other facilities. Sir, what is the Government's attitude? We discussed the JNNURM. In JNNURM, the Government is compelling; actually, the Government is blackmailing the States by saying that if they want to get the funds under JNNURM, they have to adopt certain conditions. They are saying that you have to adopt the PPP model. In Kerala, we were compelled to reduce the registration charges from 13 per cent to 5 per cent. Now this process is ongoing. Why is the Central Government compelling us like that? Land hoarding is there. People, who have money, can purchase any amount of land and they can park the money. Now, what is happening? There were certain land restrictions there. Land Reform Act was there. But, under JNNURM, the Central Government is compelling the State Government to withdraw the urban land ceiling laws, if any, from the State. They are compelling to adopt PPP

model. For example, Metro is not directly connected to poverty alleviation. But, Metro is very much indirectly helping the poor people. For the Kochi Metro, the Government of Kerala is ready to spend 50 per cent of the cost. We don't have any political difference on that issue in Kerala. We the whole party delegation, went to all offices. Even though we are ready to bear 50 per cent of the cost of Kochi Metro, the Planning Commission was not accepting that. Now, Finance Ministry is not clearing that. Instead, they are advocating the case of PPP model and they are giving the example of Hyderabad Metro. In Hyderabad, everybody knows that what happened to Satyam and Maytas. So, this was the situation about Kochi Metro. Urban transport facilities, is the responsibility of the Government because we want cheap transport service for labour. For any industry, if cost of production, cost of living goes up, industry and service sector will not grow. So, we have to provide these kinds of facilities. People coming from dormitory towns and urban suburbs should be given proper facilities to come to the city and do their job. Sir, I want to raise one important question, one of the allegations which came in many of the newspapers in Delhi. That is about one of the PPP models. Sir, some Members spoke about the Commonwealth Games, what is happening for the poor people. Outlook magazine had a report that one lakh people are losing their houses in Delhi. They are going away from the city to the outskirts. On the other hand, 15 lakh people have come to the city as new labourers. There problems are not taken care of. Near Akshardham Temple, there was a new building complex. I do not know whether the Housing Ministry or the Urban Development Ministry gave the contract. There was a company, Emaar MGF, which was given the contract for developing about 118 acres of land. For Rs.320 crores, the land was given. The tender was for constructing 1,168 flats, and DDA will get one-third as free. Then, the rest of the flats will be sold by the builder. Now, what happened was that in the name of recession builder asked for the bail-out package. The DDA took back 333 houses with a huge cost of Rs.770 crores. This was published in almost all newspapers as a serious corruption. Sir, in the name of PPP, in the name of bail-out package, the public money is going into the pockets of private people. And, the Central Government is compelling this PPP model on the States, whether it is Kerala, Tripura or any other State. Why is the Central Government compelling that PPP model has to be adopted? This kind of attitude has to be changed.

KUMARI SELJA: West Bengal is doing it happily, on its own.

SHRI K.N. BALAGOPAL: If West Bengal is doing that, then West Bengal is having clear idea. They can do that without exploitation. If China is doing that, they know how to do it. That is why, I said that in China, they are bringing people to the cities for development. But, in India, you are sending the people from the villages to the cities without giving proper facilities. That is what I am saying about the difference of China, or, Kerala, or, Bengal. So, Sir, I am not criticising.

I am sharing my ideas, Sir. With regard to the urban poverty, I want to make one suggestion. In the UPA-I Government, the National Rural Employment Guarantee Scheme was introduced. It is successful. We the left were also behind that. So, we are proud of it. Now, the Left is not there. Within one year, what has happened there? I am a junior Member. I am not going into the details. But, Sir, now, we are continuously asking for a universal employment guarantee scheme. Sir, the urban employment guarantee scheme is needed. Two-thirds of the population lives in the villages, and, one-third lives in cities. Sir, Rs. 39,100 crore have been allocated for the National Rural Employment Guarantee Scheme. My request is that, at least, 20,000 crore of rupees should be earmarked for urban employment guarantee scheme. That is the only way to protect the common people of the urban areas. Sir, I am saying this with our experience in Kerala. In Kerala, in West Bengal, in Tripura, we have introduced the urban employment guarantee schemes. Last year, we started it in Tripura. This year, in Kerala, in the name of Ayyankali Urban Employment Guarantee Scheme, we have started it, and, in West Bengal also, we have started it this year onwards.

Sir, I hope that some positive elements will come up with regard to this urban employment guarantee scheme in the reply of hon. Minister. I am concluding, Sir. We have to help the common people. It is a Constitutional liability and responsibility, in a famous case of 1980s, Olga Tellis y. Bombay Municipal Corporation, the judiciary pronounced the judgment in a very positive way. I don't know whether the judiciary will pronounce the same kind of verdict in today's situation. Students studying law are taught this important case. Sir, in this famous case, the vendors in the city were thrown out of the streets in the name of beautification. The question of personal liberty and Right to Life was before the court. The hon. Supreme Court said that the Right to Life is not the right to sleep under the bridge and beg over the street. The hon. Court observed. The right to life is not the right to sleep under the bridge and beg over the street. It is the right to live with dignity and with decent livelihood.

Sir, we have a Constitution. Everyone is saying" that we are bound by it, and, we have to uphold the principles. The Government has to take into consideration the poverty of the urban as well as the rural people, which has to be eradicated. One of the important areas, namely, housing, should also be addressed. There should be a law for restricting the land-hoarding, and, for regulating housing sector from real estate gambling, with which we can help the common people.

I think, while replying to this discussion, the hon. Minister will speak on some of the issues which I have raised. With these words, I thank you all for hearing my maiden speech.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Thanks you. Mr. Balgopal. Congratulation for you maiden speech. Now, Shri Nand Kishore Yadav.

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शहरी आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के कार्यकरण पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चाहे शहरी गरीबी हो या ग्रामीण गरीबी हो, यह देश के विकास और आर्थिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। जहां तक शहरी गरीबी का सवाल है, लगातार शहरों में लोग आकर बस रहे हैं। 1951 में गांवों में करीब 83 परसेंट लोग निवास किया करते थे और उस समय शहरों में जो लोग रहते थे, उनकी संख्या करीब 17 प्रतिशत थी। सन् 2001 में जो जनगणना हुई, उसके हिसाब से करीब 27.9 प्रतिशत लोग शहरों में रहते थे। आज 2010 चल रहा है, निश्चित रूप से शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या, 2001 की जनगणना के मुकाबले अधिक हो गई होगी। गांवों से शहरों में आकर लोगों के बसने का जो रेशियो है, अगर यही रेशियो रहा, तो आने वाले 25 वर्षों में शहरों की आबादी करीब 60 से लेकर 65 प्रतिशत हो जाएगी। जो एक बहुत बड़ी समस्या है। शहरों में खास करके गरीब तबके के लोग चाहे जिस कारण से भी आ रहे हों, यह इस मंत्रालय के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आप इनके लिए चाहे जितने भी मकान बना दें, जितनी भी बुनियादी ढांचे खड़े कर दें, चाहे सामुदायिक केन्द्र बनाने का काम करें, चाहे अस्पताल बनाने का काम करें, यह समस्या खत्म होने के बजाए बढ़ ही रही है। आपका मंत्रालय इनके लिए मकान बनाने का काम कर रहा है, बैंकों से सस्ते ब्याज दर पर लोन देने का काम कर रहा है, लेकिन जहां आप समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, चाहे शहरी गरीबी का सवाल हो या शहरों में जो लोग आकर बस रहे हैं, उनके मकानों का सवाल हो, आपकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जहां तक मैं इसका जो मूल कारण समझता हूं, जैसा कि श्री करीमपुरी जी ने जब इस चर्चा की शुरुआत की थी, तो उन्होंने संकेत करने का काम किया था, वह यह है कि पहले देश की जो आबादी थी, उसमें जो अधिकतर आबादी गांवों में रहती थी, जो खेती करने का काम करती थी, जब कि आज कल खेती घाटे का काम हो गया है, इसलिए लोग कृषि के प्रति उदासीन हो गए हैं। इसके अनेक कारण हैं। उन्हें खाद, पानी, बिजली, कीटनाशक दवाएं, आदि नहीं मिल पा रही हैं, उन्हें उनके उपज का उचित

मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस पर चर्चा करने लगे, तो यह एक लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन एक प्रमुख कारण यह है कि इस देश के अंदर लोगों का खेती के प्रति जो मोह भंग हो रहा है, उसके कारण देश के अंदर बेरोजगारी पैदा हो रही है और बेकारी की समस्या पैदा हो रही है। कृषि का जो सैक्टर है, वह इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, उसको दूर करने का काम करता था। आज लोग खेती की तरफ से हट कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और शहरों में आकर वे लोग छोटे-मोटे काम करने का काम करते हैं। मजदूरी करने का काम करते हैं या घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं। वे लोग यहां आकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने काम कर रहे हैं। चाहे डीडीए की जमीन हो या रेलवे की जमीन हो, वे लोग उस पर अतिक्रमण करने का काम कर रहे हैं। पहले महानगरों - दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, आदि में लोगों का पलायन होता था, लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि देश के छोटे-छोटे शहरों में भी इस तरह की समस्या खड़ी हो गई है। लोग वहां आकर झुग्गी-झोंपड़ी बनाकर उसमें निवास करते हैं। देश के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या है और आज इससे निपटने की आवश्यकता है। यद्यपि मंत्रालय इसके लिए काम कर रहा है, लेकिन फिर भी यह समस्या बरकरार है और आने वाले समय में यह समस्या और बढ़ेगी।

महोदय, जहां तक झुग्गी-झोंपड़ी और स्लम बस्तियों का सवाल है, वहां पर बुनियादी सुविधाओं का सवाल है, चाहे सड़क का सवाल हो, चाहे उनके बच्चों के लिए स्कूल का सवाल हो, चाहे सामुदायिक केन्द्र का सवाल हो, चाहे गटर का सवाल हो, चाहे रोशनी का सवाल हो, हम उनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सके हैं। इसके लिए अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि माननीया आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री जब अपना उत्तर दें, तो यह बताने की कृपा करें कि शहरी गरीबी की जो परिभाषा है या जो शहरी गरीब लोग हैं, इसको निर्धारित करने के लिए कौन सा मानक है, जिसके आधार पर आप उन्हें शहरी गरीब मानते हैं।

महोदय, इस देश में गरीबों की पहचान करने के लिए जितनी भी समितियां बनीं कि इस देश में कौन गरीब है और कौन-कौन गरीबी रेखा के नीचे है, इन सबने अपना अलग-अलग नज़रिया, अलग-अलग दृष्टिकोण दिया है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहा कि इस देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों की संख्या 37.2 परसेंट है। जो रोज़ाना 19.3 रुपए कमाता है या उससे कम कमाता है, उसको उन्होंने शहरी गरीब माना है। ग्रामीण क्षेत्र में जो 15 रुपए कमा रहा है, उसको इस तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण गरीब कहा है। 2007 में माननीय अर्जुन सेनगुप्त की रिपोर्ट में कहा गया कि इस देश में 77 परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं। जो 20 रुपए रोज़ कमाता है या 20 रुपए से कम कमाता है, उसको उन्होंने गरीबी रेखा के नीचे माना है। इसी प्रकार एक एन.सी. सक्सेना समिति थी। उसने कहा कि इस देश में करीब 50 परसेंट लोग गरीब हैं। रिज़र्व बैंक की एक रिपोर्ट है जो 41.6 परसेंट मानती है, तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस देश में शहरी गरीब आप किसको मानते हैं, यह बताएं। ...(**समय की घंटी**)...

सर, जहां तक आर्थिक रूप से कमज़ोर और निम्न वर्ग में आवास की कमी का प्रश्न है, आज भी चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हों, उनके लिए आवास एक बहुत बड़ी समस्या है। केन्द्र सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों तथा निम्न वर्ग के लिए विशेष रूप से, किफायती आवास मुहैया कराती है, लेकिन पूरे देश के

स्तर पर देखा जाए तो समाज के सभी वर्गों को किफायती मूल्य पर जीवन आश्रय और सेवाओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पिछले एक दशक के दौरान सारे क्षेत्रों में आवास की कमी बढ़ गई। राज्य सभा में दिनांक 4 मार्च, 2010 को एक Unstarred Question के उत्तर में सरकार ने स्वयं कहा है कि दसवीं योजना के लिए आवास संबंधी कार्य दल ने अनुमान लगाया है कि 90 परसेंट आवासीय समस्या सभी कमजोर वर्गों से संबंधित है। कार्य दल ने यह भी अनुमान लगाया था कि दसवीं योजना के शुरू में 8.89 मिलियन शहरी आवासों की कमी है। वर्ष 2006 में शहरी आवासीय कमी के आकलन के लिए मंत्रालय द्वारा गठित एक तकनीकी समूह ने यह अनुमान लगाया कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में 2007-08 के अंत में भीड़भाड़ और पुराने घटकों को ध्यान में रखते हुए देश में कुल आवासी कमी 27.71 मिलियन थी।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपका मंत्रालय प्रयास कर रहा है। जो निम्न वर्ग के हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको आप आवास बनाकर दे रहे हैं, बैंकों से लोन दिलाने का काम आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जहां आप उनको बसाने का काम कर रहे हैं, जिस स्लम बस्ती को मान्यता देने का काम आप कर रहे हैं, ...(**समय की घंटी**)... उनको प्रॉपर्टी का हक देने का भी आप काम करें। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI N. BALAGANGA (Tamil Nadu): Sir, I thank you for having given me the opportunity to participate in the discussion on the working of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation. Food, clothing, and housing are required in that order for fulfilling the aspirations of the people.

The demand for housing is increasing day by day due to the growth of population, rapid pace of industrialization, and urbanization. Cities and towns of India constitute the world's second largest urban sector. The Government of India has successfully implemented the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. It is extended to all the districts. It has covered almost 4.5 crore households.

Even then, the migration of villagers could not be stopped. They are going towards urban centres in search of better jobs. Sir, as per 2001 population Census, 285.35 million people live in urban areas which constitutes 27.8 per cent of the total population of India. The slum population is also estimated to be 61.8 million. The rising urban population has also given rise to increase in the number of urban poor. Added to this in the changing circumstances, there has been increased demand and desire to own houses.

Sir, the matters pertaining to poverty alleviation and housing have been assigned to the State Governments by the Constitution of India. The Constitution (74th Amendment) Act also delegated

many of its functions to the local bodies. Although these are essentially State subjects, the Government of India plays a coordinating and monitoring role, and supports programmes through its Centrally-sponsored schemes. Here, I congratulate the Union Government for introducing and implementing many schemes like Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) which comprises two sub-missions, namely, Basic Services to the Urban Poor and Integrated Housing and Slum Development Programme, Rajiv Gandhi Awas Yojana, Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana and National Policy on Street Vendors.

Sir, the Ministry has selected 65 cities in the country for implementation of Basic Services to Urban Poor mission. In Tamil Nadu, Chennai, Madurai and Coimbatore have been selected. I urge upon the Government to include Tiruchirapalli, having a population of eleven lakh, in the list of cities for implementation. It is also a central part of Tamil Nadu. Sir, there is a rule stipulated in the BSUP and IHSDP. The targeted beneficiaries are slum dwellers and urban poor. While a minimum of 12 per cent contribution is stipulated to be borne by the beneficiary under Basic Services to Urban Poor mission, it is ten per cent under the Integrated Housing and Slum Development Programme in the case of SC, ST, BC, OBC and other weaker sections. Sir, I honestly and sincerely inform the Government that the poorest of the poor who have been living on the platforms, on the river bed sides, without proper civic amenities could not cope up with the conditions of the Government. Don't be firm on this commitment. If you are firm on this commitment, definitely, the aim of the Government to provide houses with proper amenities will become futile. Sir, I have come to know that the Government of India have instructed the Chief Ministers to amend local laws to ensure that the Master Plan of metro and other cities have 20 to 25 per cent reservation both in land and floor space index to house the urban poor in the cities.

In this context, I would like to inform the Minister about one thing. For example, in Chennai, the Chennai Metropolitan Development Authority is there which is a governing body that regulates construction activities in the city limit area. It has separate building control rules. There is a provision in the building control rules which has been in force for a long time which says that the building promoters and the Government agencies should provide open space reserve. If the plinth area is between 3,000 to 10,000, 1/10th of the portion of land area should be reserved and should be given to the Municipal Corporation or the 1/10th value of the land should be deposited into the Government

treasury. If the plinth area is more than 10,000, it is compulsory that the builder or the Government agency which construct it, they should hand over 10 per cent of the reserve land which is called open space. If this is the condition, the Government cannot ask the builders to reserve another land for open space for providing houses to the poor people.

Sir, Rajiv Awas Yojana which aims at making the country slum-free, has some salient features. One of the important salient features is assigning property rights to the slum-dwellers. Here, I would request the hon. Minister to give suitable instructions to the State Government and the concerned officers to be more vigilant in assigning title deeds to the beneficiaries. And I also request you to incorporate some conditions while giving the sale deed that the beneficiary should not transfer the rights to another person. This is a must. The Government should ensure this.

Another thing is, Sir, the Union Government is allotting huge sums of money for the Centrally-sponsored schemes, particularly, the poverty alleviation scheme. I have been given to understand that there are two steering committees, one headed by the Chief Minister of the State and the other at the Central level which would monitor the implementation of programmes. I wish to bring to the notice of the Government that under the JNNURM, the Government of Tamil Nadu has gone on constructing houses at Coimbatore. The place where construction activities are going on, is unfit for construction because the land on which construction is going on is a water body where construction activities are banned ...*(Interruptions)*... Despite this fact, the state authorities proceeded with the construction of the houses with the result that in two blocks, hundreds of houses have collapsed. ...(**Time Bell rings**)... This kind of irresponsible attitude of the authorities should not only be condemned but also punished. I request the Government of India to periodically monitor the scheme through the designated officers of the Ministry. ...*(Interruptions)*... With these words, I conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri N.K. Singh - Not there. Shri Ranjitsinh Vijaysinh Mohite- Patil. You have five minutes. That is your time.

SHRI RANJITSINH VIJAYSINH MOHITE-PATIL (Maharashtra): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the working of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation and I would like to be very brief on the issue. Migration is taking place in a big way and the hon. Members have stated the statistics of urbanization. I would like to pin point

the issue. There are various issues. Why is the migration taking place? It is because of the problem of unemployment; it is because of lack of opportunities in the rural areas.

And, at the same time, the main issue is irrigation. The dams that were built were previously meant for irrigation, but, now, they are converted into drinking water reservoirs. So, the water that was used for irrigation has been reduced or is no more there. So, the migration is taking place. At the same time, some urban issues are being raised or we are having a discussion on them.

Sir, I would like to be specific, and I would suggest some things, that to deal with poverty in the urban areas, I think, we should have a policy on three or four issues, relating to night schools, night colleges, industrial training institutes, service sector and service industry, a policy that can help the youths and the unemployed people living in cities or in towns. If they have a night school or a night college or an industrial training institute, they can work during the daytime and they can study during the late hours; that can help them over the period. The service industry which is related to hospitals, hotels, restaurants, and information technology should be promoted and should have a policy which can go across all the towns and the cities.

At the same time, I would like to pinpoint the historical places and the religious places. The Government should start centres for the guides so that it can engage the youths and the young people to generate employment in that industry also, in that sector also. Not to stretch my speech, as we are having a discussion on the also, I would only suggest low-cost housing, low-interest rate housing, affordable rehabilitation and rental housing policy also. This is in brief. But I would like to pinpoint the same thing, that water is the main issue; it is not an urban issue alone. It is because of urbanization that the problem is taking place. So, the urban policy should have a water audit law. That is being used in the towns or in the cities. For urban areas, there should be a water audit policy; that should be promoted. That's it. And the basic cause is water, the irrigation, the unemployment problem in rural areas. So, the urbanization is taking place. I am sure, the hon. Minister will look into the matter. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you very much, Mr. Patil, for sticking to the time. Now, Shri M.P. Achuthan.

SHRI M.P. ACHUTHAN (Kerala): Sir, we are discussing one of the most serious issues facing the country, the housing and the Urban Poverty Alleviation Programme. Many of the aspects have

already been dealt with by the Members who highlighted the problem. And Comrade Balagopal has pointed out the experience of Kerala and how we are tackling the housing problem in Kerala. But some of our State Governments and rulers are seeking some easy solutions to eradicate slums and beggars from our cities. In Delhi, it is reported that the Government is planning to deport the beggars from Delhi during the Commonwealth Games to give a false impression that all is well in Delhi, and in India. It is easy for any Government to have such a utopian idea of eradicating poverty and slums in India. As reported by the Delhi Municipal Corporation, today, 49 per cent of population in Delhi is living in slums and *jhuggis*.

There are no arrangements for lifting garbage. Then, you can imagine the health hazards that such people who are living in slums and jhuggies are facing. Though we have got the Rajiv Gandhi Awas Yojana and the Minister has repeatedly said that within five years we would clear the slums, is it possible with this kind of allocation and machinery? What I suggest is that we, the Parliament, have to pass a Constitutional (Amendment) Bill making right to shelter as a fundamental right of our people. We have already made right to education as a fundamental right. If we make right to shelter as a fundamental right, then the Government and the Parliament will be legally bound to find out ways and means to provide housing to our people. Today, as far as housing is concerned, what we see in the print media advertisements is mainly housing for the upper middle class and the affluent sections of the society. Crores of rupees are being spent on housing. If we make such a law, then we can levy a cess on the houses in the urban areas, maybe, having a plinth area of 2,000 square feet and more. We can spend that amount for providing shelter to the common people and slum eradication programme. Now we see that big real estate firms are spending crores of rupees for sponsoring IPL teams or IPL games. The Government has to levy some cess on big real estate firms and that money has to be used for providing houses to the poor.

As Shri Balagopal has pointed out, housing should be taken up as a mass or popular movement involving the local administration, the State administration, the NGOs and the Central Government. Only then can we succeed. We have to make it a mass or popular movement providing houses to the poor needy people. Otherwise, we can't provide housing and the migration from the rural areas will continue. ...(**Time bell rings**)... I am just concluding, Sir. It is a phenomenon not only in

India but all over the world. If we make life in the rural areas affordable, then only we can stop migration. To provide employment in the urban areas, the Employment Guarantee Scheme has to be implemented in urban areas also. With these words, I conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you very much. Dr. Ashok S. Ganguly. He is not present. Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. The cities and towns in India contribute over 50 per cent of the countries GDP and form the centre of economic growth. For this, the cities have to realise their real potential and prove themselves as the real engine of growth. The Government should concentrate on providing infrastructure and the basic amenities for the poor in the urban areas.

I don't want to elaborate much because my colleagues have spoken at length earlier. The Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission was launched on 3rd December, 2005. The Mission comprises two sub-missions: one BSUP and the other UIG. I would like to say one important thing about this. Under the JNNURM Scheme, the total amount, which was budgeted for the year 2009-10, was Rs. 11,619 crores. However, this estimate was revised down to Rs. 6,333 crores, that is, 54 per cent of the budget estimate. Despite this, the allocation for the year 2010-11 is again Rs. 11,619 crores. So the Government of India is very much particular in allocating the necessary funds; whereas, the revised estimate shows that the allocated amount has not been properly utilized. For that, the reasons ascribed by the Government are shortfall in allocation of funds and slow pace of submission of quality project proposals by States. I would like to submit to the hon. Minister that the Ministry of Rural Development has recently issued a Circular saying that apart from the Committee, if the Members of Parliament propose some specific places where the hand pumps could be installed, they should be given priority. So, I would like to know from the hon. Minister: if the Members of Parliament give some proposals, which could be accepted, which are feasible, will that be taken into account? Sir, only 13 per cent of the funds allocated for Delhi had been released as on July last year. I would like to say that under the JNNURM Scheme, the total allocation is around Rs. 50,000 crores for seven years, that is, 2005 to 2012 and under the UIG Scheme, it is Rs. 25,000 crores for the whole

seven years. Out of the total of 961 detailed project reports submitted by the States to the Ministry up to June, 2009, 463 projects were approved. As of February, 2010, 523 projects have been approved and at the end of 2009, a total of 48 projects had been completed. According to the Government, subsequent installments of additional Central assistance for projects are released only upon receipt of proper Utilisation Certificate from State Governments. Sir, the slum dwellers' problem cannot be looked as just a housing problem. For a slum dweller, the slum where he is living, it is not only a house; often it is a small factory, a shop or something. We have been talking about urban development for the last 15 years. Now the situation has worsened and the slums have increased by 15 times in spite of these efforts. The Government of India has taken many initiatives and is extending to the maximum not only some schemes but also enough allocation of funds. But my query to the Minister is this. For four schemes, that is, the SJSRY, in the year, 2007-08, the Low Cost Sanitation, the Interest Subsidy Scheme for Housing the Urban Poor and the Rajiv Awas Yojana, the budget estimate was Rs. 509.75 crores and the revised estimate was Rs. 509.75 crores. But, next year, in 2008-09, the budget estimate was Rs. 856.05 crores, whereas, the revised estimate was Rs.676.89 crores. More or less, the revised estimate is less by 32 per cent. In 2009-10, the budget estimate was Rs. 857.97 crores and the revised estimate was 582.05 crores. Especially, under the Interest Subsidy Scheme for Housing the Urban Poor, the amount released is only Rs. 5 crores. Out of the fund of Rs. 180.59 crores, the amount released is only Rs. 5 crores. The reason may be any. But as it was pointed out here, the proposals given by the State Governments have not been approved by the Central Government which means that it does not fulfill the necessary obligations that they deserve.

Now, I would like to say about Tamil Nadu. I have always suggested that in a federal structure, the State Government has equal responsibility in everything. When the Central Government is extending so many schemes, giving so much of funds, we should know how the State Governments are co-operating with it. Now, we have the BSUP and IHSDP which aim at the integrated development of housing and slum infrastructure. Under the BSUP, the Government of India has allotted a sum of Rs. 1,382 crores for the mission period, 2005-12, as additional Central Assistance to Tamil Nadu. So far, 51 projects have been approved at a total project cost of Rs.2,327.30 crores, involving Central assistance. Now, the Government of Tamil Nadu has contributed its share, unlike other States which have been mentioned. I do not want to name the States which have not utilised the fund. I do not want to go into the details. But the Government of Tamil Nadu utilises the Central Assistance as well as it contributes its share.

Also, we have the Integrated Low Cost Sanitation Scheme, which is for construction of new toilets. In places where the households of economically weaker sections have no toilets, this will help in overall sanitation in towns. The Government of India's share is 75 per cent; the Government of Tamil Nadu's share is 10 per cent and the beneficiary's contribution is 10 per cent. In the first phase, it has been proposed to take up toilets in mission cities and urban agglomeration, namely, temple towns and towns of tourist importance. The Detailed Project Reports, received from 19 urban local bodies, are under scrutiny.

Coming to the Basic Services to the Urban Poor (BSUP), there are already three districts included, as mentioned earlier by my colleague. These are Chennai, Coimbatore and Madurai. I would urge upon the Ministry to include Tiruchi, which deserves to be included in this list. Then, the Integrated Housing and Slum Development Programme has also been successfully implemented in the State of Tamil Nadu. I hope the Minister would appreciate the schemes that are being undertaken there. Then, coming to Solid Waste Management, one of the essential ingredients in this scheme is that based on the Municipal Solid Waste Management and Handling Rules, 2000, the Government of Tamil Nadu has issued instructions to all the urban local bodies to draw an Action Plan to implement the Solid Waste Management Rules. The Government has sanctioned an amount of Rs.4.75 crores for the purchase of land for the compost yard in 68 urban local bodies under the Part II Scheme...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please wind up.

SHRI TIRUCHI SIVA: Having said all these, I would like to say that urbanization, though it has increased substantially, that is, 15 times than it was 15 years ago, thanks to the schemes which are being implemented and the initiatives undertaken by the Minister of Housing and Urban Poverty Alleviation, I hope, under the UPA-II, our mission will get accomplished, and my State, Tamil Nadu, will give the fullest co-operation, as we are doing now.

सुश्री सुशीला तिरिया (उड़ीसा) : धन्यवाद सर। सर, मैं आपकी permission से Ministry of Housing and Poverty Alleviation के ऊपर discussion में अपने आपको शामिल करने के लिए खड़ी हुई हूं। इस विषय पर बोलने में मुझे बहुत खुशी है। इस urban housing and poverty alleviation पर बोलने से पहले मुझे slum में रहने वाले एक भाई का शेर याद आता है। इसलिए मैं उसी शेर से शुरू करना चाहती हूं।

"आपके शहर में आए, तो गांव से भी गए,

मकान की आस में गांव के पेड़ों की छांव से भी गए।"

मैं यह कहना चाहती हूं कि जितना भी discussion हुआ, लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं और शहर में वे केवल रहने-सहने के लिए नहीं आ रहे हैं। 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। गरीब लोग गांवों में NREGS Programme चालू होने के पहले रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में शहर आते थे। शहर में वे बेचारे कहीं थोड़ी-बहुत जगह ढूंढ कर, अपनी जगह बना कर रहते थे और कपड़े और रोटी की तलाश में रहते थे।

यह बजट बहुत अच्छा बजट है और इसके लिए मैं मैडम शैलजा जी को बधाई देना चाहूंगी। उनमें कुछ करने की लगन है, इसलिए 2010-11 के बजट में उन्होंने इसमें 1007.3 करोड़ रुपया रखा है। बहुत सारी स्कीम्स के तहत Special Central Assistance रखी गई है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगी। जवाहरलाल नेहरू नवीकरण योजना के तहत यह बहुत लगन से काम कर रही हैं एवं इसमें उन्होंने लोकल बॉडीज़ और छोटे-छोटे शहरों को भी शामिल किया है। स्टेट गवर्नमेंट जिनको भी इस योजना के लिए रिकमैंड करेगी, उनको इसमें शामिल किया जाएगा, फिर वहां की पॉपुलेशन चाहे जितनी भी हो।

अर्बन डेवलपमेंट और पावर्टी एलिविएशन के संबंध में मेरी अभी तक की जो जानकारी है, उसके अनुसार उसमें केवल महानगरों और नगरों को ही शामिल किया गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नवीकरण योजना के तहत छोटे शहरों को भी शामिल किया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसमें 50,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया रखा है। यह सिर्फ सैंट्रलाइज्ड पॉलिसी ही नहीं है, डीसैंट्रलाइज्ड पॉलिसी भी है। छोटे शहरों को डेवलप करने से ही बड़े शहरों में भीड़ कम होगी। अभी तक लोग गांवों और देहातों से केवल रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में ही शहरों की ओर आते थे। स्टेट हैडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर और ब्लॉक हैडक्वार्टर में कुछ लिमिटेड अनुमानित पॉपुलेशन रखी गई है। आज के समय में अर्बन पॉपुलेशन लगभग 300 मिलियन से भी ज्यादा है। 2051 में देश की जितनी पॉपुलेशन होगी, उनमें आधे से अधिक शहरों में रह रही होगी। इस संबंध में मैं अपने कुछ विचार भी रखना चाहूंगी। जवाहरलाल नेहरू नवीकरण योजना के तहत जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही गई है, वह बहत ही स्वागत योग्य है। देश में 26.71 मिलियन की हाउसिंग शॉर्टेज कही गई है और इस योजना के माध्यम से लोकल बॉडीज़ को ही पावर दी गई है। वे स्वयं अपनी सैनीटेशन पॉलिसी और प्लान बना करके आपके पास भेजेंगे, यह बहुत ही अच्छी बात है। आप यहां से नैशनल पॉलिसीज़ बनाते हैं, चाहे वह सैनिटेशन के संबंध में हो, चाहे वह सिटी प्लान के संबंध में हो, लेकिन इस योजना में यह बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसे छोटे शहरों, डिस्ट्रिक्ट या टाउन्स पर थोपने नहीं जा रहे हैं। इसके विपरीत आप उन्हीं से इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग मांग रहे हैं कि किस तरह से वहां नवीकरण होना चाहिए, किस तरह से सैनिटेशन के संबंध में काम होना चाहिए और पीने के पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वेस्ट मैनेजमैंट की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, इत्यादि। इस तरह लोकल बॉडीज़ को ज्यादा पावर देने के लिए आप उन्हीं से प्लान मांग रहे हैं।

स्टेट गवर्नमेंट्स की लोकल बॉडीज़ को मार्च महीने में आपने एक चिट्ठी इश्यू की थी कि जवाहरलाल नेहरू नवीकरण योजना के तहत डिस्ट्रिक्ट लैवल पर UIG और BSUP में रिव्यू कमेटी और प्लानिंग कमेटी की मोनिटरिंग

का जो प्लान बनाया जाएगा, उसमें एमपीज़ और एम.एल.एज. को भी शामिल किया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक इसमें किसी भी एमपी या एमएलए को शामिल नहीं किया गया है। अर्बन मिनिस्ट्री के जिस प्लान के तहत यहां से पैसा जाता है, उसमें वहां के डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लैवल के लोकल एमपीज़ और एमएलएज़ रिप्रैज़ेंट करते हैं। यहां मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब पार्लियामेंट में एमपीज़ उस स्टेट को रिप्रैजेंट करते हैं, तो वहां की लोकल बॉडीज़ की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए भी एमपीज़ को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बाकी शहरों के साथ-साथ बॉडीज़ के जो शहर हैं, उनकी पृष्ठभूमि बनाने के लिए वे भी अपने व्यूज़ दे सकें।

आज के समय में शहरों में स्लम्स बहुत बढ़ गए हैं और स्लम्स में ज्यादातर डिप्राइव्ड और बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहते हैं। गांवों में आपने बिलो पॉवर्टी लाइन और एबव पॉवर्टी लाइन बनाया है, लेकिन शहरों में आपने मिनिमम इन्कम ग्रुप और लोअर इन्कम ग्रुप बनाया है।

सर, मैं यह कहना चाहूंगी कि आज इस हाउस में जितने भी हम एम.पी. रहे यह सुनते रहे कि अक्सर किसी-न-किसी प्रकार के हादसे स्लम में होते हैं। स्लम में कुछ न कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं, अखबार के माध्यम से इस हाउस में भी वे चर्चा आती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि यह घटना घटने से पहले ही क्यों न आप इसकी अच्छी पृष्ठभूमि तैयार करें जिससे कि जिन उद्देश्यों के लिए यह प्लान या स्कीम है, उनका लाभ ग्रास रूट में व्यक्ति को वाकई पहुंचाया जा सके।

सर, बारिश के दौरान दिल्ली में जहां स्लम नहीं है वहां बारिश का बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और कई बार तो सारे रास्ते में गाड़ियां जाम हो जाती हैं। उस समय बारिश से स्लम इलाके के रास्ते डूब जाते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि आपके poverty alleviation के तहत बड़े या छोटे शहरों में स्लम को इधर-उधर बिखरा हुआ न रखते हुए उसके लिए एक अच्छी योजना होनी चाहिए। शहर के आसपास पांच-दस किलोमीटर की दूरी में आपने slum development के लिए जमीन भी रखी है, जो आपने affordable or sustainable मकान बनाने के लिए 25 परसेंट रखा भी है, तो शहर से पांच-दस किलोमीटर की दूरी पर इसी तरह की कोई जमीन लेकर उनके लिए अच्छा प्लान बनाएं। वहां आप उनके लिए अच्छे रास्ते, सेफ्टी, लैट्रिन और ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था रखते हुए पक्के मकान बनाने की योजना इसी प्लान के तहत रखें ताकि आपका तथा आपके डिपार्टमेंट का स्लम फ्री शहर का जो सपना है, वह साकार हो सके। आज शहर के अन्दर या राज्यों की राजधानियों में या हर बड़े-बड़े शहर में जहां भी जगह मिली वहां पर एक झुग्गी बन गई और एक स्लम बन गया। यह शहर की सुन्दरता को भी खराब कर रहा है। मैं इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि अगर हम लोग गरीबों के लिए कुछ योजनाएं बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए शहरों के आसपास पक्के मकान की व्यवस्था करनी चाहिए। आपने जो बेसिक सर्विस रखी है, वे सारी सुविधाएं भी वहां रखनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जहां पर स्लम है वहां वेस्ट मैनेजमेंट बहुत होता है। वहां पर हाइजिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहती हूं कि शहर में वेस्ट मैनेजमेंट की जगह की भी अच्छी

प्लानिंग होनी चाहिए। शहर में जितनी बेसिक नीड्स हैं, जैसे आज सेनिटेशन की बेसिक नीड है, तो वहां वेस्ट मैनेजमेंट की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं जिस शहर में रहती हूं, उसी शहर में हो सकता है ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं खत्म कर रही हूं। ...(**व्यवधान**)... गवर्नमेंट ने आपके पास वह जरूर भेजा होगा। आज वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम है। हर साल कई छोटे शहरों में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से बीमारियां फैलती हैं। इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट को अरबन डेवलपमेंट के अन्दर आप ऐसी जगह पर रखिए, ताकि उससे जो बीमारियां फैलती हैं, वे गरीबों में न हो पाएं।

सर, अगली बात मैं यह कहना चाहती हूं कि आप NAMT रोजगार योजना के तहत affordable or sustainable मकान बनाकर गरीबों को और SC/ST को देने जा रहे हैं। मैं आपको इसी विचार के साथ यह निवेदन करना चाहती हूं कि दिल्ली में अभी ST का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है, इसलिए अब दिल्ली में ST का रिजर्वेशन नहीं है। कोई बेचारा गांव से आया और इधर ही बस गया। वह अपने राज्य में रिजर्वेशन में आता है, वहां वह Caste Certificate avail करता है, लेकिन उसे वह दिल्ली में avail नहीं कर सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य से आया हो। मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर वह अपने राज्य का Caste Certificate दिल्ली में प्रोड्यूस करना चाहे तो उसको दिल्ली में क्यों नहीं मानते हैं या उसको क्यों नहीं count करते हैं। यह भी विचार करने का एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में एस.टी. बिल्कुल भी नहीं हैं, यह कहना गलत है, इसलिए दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में उनके रिजर्वेशन को खत्म कर देना भी गलत है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि आपको SC, ST और physically handicapped persons के लिए इसमें कुछ affordable position में मकान देने चाहिए। ....(**समय की घंटी**).. सर, मैं अब खत्म कर रही हूं। मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि SC/ST को बड़े शहरों में आने के लिए मना है। उनके लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है या Caste Certificate है, उसको आप काउंट नहीं कर रहे हैं। How can you give them a house in an affordable position ***...(Interruptions)...*** ...(**Time bell rings**)... एक मिनट, सर। ...(**व्यवधान**)... अंतिम बात है, सर। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please sit down, Ms. Tiria.

MS. SUSHILA TIRIYA: Sir, I will finish in just one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, please listen to me and sit down since at five o' clock, we need to take up Half-an-Hour Discussion.

MS. SUSHILA TIRIYA: Sir, okay, thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Discussion on half-an-hour is the next item. We have to finish it in just half-an-hour. Each speaker will speak for not more than three minutes. Shri Santosh Bagrodia has gone out seeking my permission. Now, Shri Rajiv Pratap Rudy.